(b) if so, the details of such demands received for employees, organisation-wise;

(c) whether Government have issued orders in this regard so far; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir. The newspaper employees have been demanding implementation of a pension scheme.

(b) The National Union of Journalist demanded pension at the rate of 50% of the average monthly emoluments drawn during the last 12 months. The All India News Paper Employees Federation wanted the pension scheme to cover both the working Journalist and non-working Journalist employees. The Indian Journalist Association wanted the pension scheme to be framed on the basis of Employers' contribution alone.

(c) and (d) The pension scheme has since been framed and is already under implementation w.e.f. 16.11.95. The Scheme is applicable to all the EPF subscribers including the newspaper employees covered under the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952. The Scheme, inter-alia, provides for payment of monthly pension in the contingencies of superannuation, retirement, permanent total disablement, death etc. Minimum 10 years' contributory service is necessary for being entitled to pension.

Infrastructural constraints

817. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it has been apprehended that current industrial boom may not be sustained if the existing infrastructural constraints are not removed by Government on a priority footing;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to take some measures in this regard;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN) (a) to (c) Development of a strong economic infrastructure in sectors like power, transport and communicatin is considered critical for sustained industrial growth. The Government is already considering extensive application of market mechanism in these sectors through deregulation of production and distribution. Foreign investment in these sectors is also being encouraged to supplement domestic resources.

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सरकारी क्षेत्र का इकाइयों में पूंजी-निवेश

818. **श्री राम जेटमलानी:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, देश में सरकारी क्षेत्र में अनेक औद्योगिक इकाइयां कार्यरत थीं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 में ऐसी कुल कितनी इकाइयां थीं तथा उनमें कुल कितनी पूंजी निवेषित थी;

(ग) वर्ष 1995-96 के अंत में, सरकारी क्षेत्र की इन इकाइयों की संख्या कितनी थी तथा उनमें कितनी पूंजी निवेशित थी;

(घ) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इन इकाइयों में कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1995-96 में कुल कितने-कितने कर्मचारी इन सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत थे?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) जी हां, 31.3.1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 246 उद्यमों में 113896 करोड़ रु० का निवेश किया गया था। 31.3.1995 की अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है जिसके अनुसार सरकारी क्षेत्र के 245 उद्यमों में किए गए निवेश की राशि 172438 रु० थी।

(घ) और (ङ) 31.3.1991, 31.3.1992, 31.3.1993, 31.3.1994 तथा 31.3.1995 के अंत तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 23.06 लाख, 22.80 लाख, 22.21 लाख, 21.53 लाख और 21.08 लाख थी।

विद्युत परियोज़नाओं के लिए कोयले का आवंटन

819. श्री रामजीलाल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास इस समय अच्छी किस्म का कोयला उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो गत् दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को कितना-कितना कोयला प्रदान किया गया;

(ग) क्या इस कोयले के प्रयोग के कारण विद्युत का कम उत्पादन होता है; और

(घ) प्रत्येक विद्युत परियोजना को अच्छी किस्म के कोयले की आपूर्ति कब तक की जाएगी?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) विद्युत गृहों के लिए उयुक्त गुणवत्तवाला कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(ख) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरा विभिन्न विद्युत संयंत्रों को आपूर्तित किए गए कोयले की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) तापीय विद्युत गृहों को अधिकांशतः पर्याप्त मात्रा में तथा सहमति हुई कोयले की मात्रा की आपूर्ति कर दी गई है, जिसके लिए उनके बायलरों को अभिकल्पित किया गया है। विद्युत गृहों को आपूर्ति किये जा रहे कोयले की मात्रा के संबंध में आमतौर पर, यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वह कोयले में अवशिष्ट सामग्री के होने तथा बड़े आकार के कोयले की आपूर्ति किये जाने के संबंध में भी होती है। इन शिकायतों की प्रत्येक मामले में गुणवगुण आधार पर समीक्षा की जाती है और उपभोक्ताओं की शिकायतों को कम किये जाने हेतु कार्रवाई की जाती है।

विवरण

विद्युत गृहों के आपूर्तित किया गया कोयला

(लाख टन में)

राज्य	1994-95	1995-96
पश्चिम बंगाल	152.52	164.20
बिहार	63.70	76.23
उत्तर प्रदेश	289.48	339.92
उड़ीसा	15.59	29.92
मध्य प्रदेश	285.18	308.46
महाराष्ट्र	253.43	277.62
गुजरात	128.55	136.84
राजस्थान	33.28	39.10
दिल्ली	61.45	49.84
पंजाब	58.69	63.83
हरियाणा	28.02	25.62
तमिलनाडु	101.13	101.67
आंध प्रदेश	183.96	222.75
कर्नाटक	33.21	36.67
असम	3.18	4.01
अन्य	—	0.77*

*विभिन्न विद्युत गृहों के मामले में समायोजन आधनी।

Decline in procurement target for wheat

820. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether procurement target for wheat set by his Ministry has been severely upset with trends showing a decline of 20% in procurement during current rabi season;

(b) if so, main reasons for the short fall;

(c) the extent to which there has been a short fall of wheat;

(d) if so, whether Government is confident of achieving target of 13 million tonnes; and

(e) whether the latest trends show that wheat and rice production has already crossed the target?